

मुख्य समाचार :-

- मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा और देहरादून शहर में दस पिंक ई-बसें संचालित करने की घोषणा की है।
- प्रदेश में ग्लेशियर व ग्लेशियर झीलों की निगरानी एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वभर में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया जाएगा।
- 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत 'युवा संगम' चरण-7 की मेजबानी का जिम्मा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है।
- मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आज प्रदेश के कई जिलों में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

रोडवेज बस सेवा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा और देहरादून शहर में दस पिंक ई-बसें संचालित करने की घोषणा की है। इस योजना का प्रदेश की साढ़े छह लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज की बस में सफर निशुल्क सफर और ई-पिंक बसों के संचालन से शहरी क्षेत्र की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देहरादून में ई-बस संचालन के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह योजना शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने हमेशा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार हर उम्र की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा और पिंक ई बस सेवा के जरिए महिलाएं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगी।

ग्लेशियर झीलों की निगरानी

प्रदेश में ग्लेशियर व ग्लेशियर झीलों की निगरानी एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए विश्वभर में उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया जाएगा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों की स्थिति में होने वाले बदलावों की वैज्ञानिक निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि ग्लेशियर झीलों की निरंतर एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना बेहद जरूरी है। ग्लेशियर झीलों के जलस्तर, आकार, जलभराव की स्थिति और उनमें होने वाले संभावित बदलावों पर लगातार नजर रखी जाए। इसके लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, सेंसर आधारित निगरानी तथा अन्य आधुनिक तकनीकों की संभावनाओं का अध्ययन कर इन्हें आवश्यकता के अनुसार अपनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम भी स्थापित करने को कहा।

महायोजना

प्रदेश सरकार ने धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास की कवायद तेज कर दी है। आवास विभाग ने ऋषिकेश महायोजना को अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में देहरादून, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के संबंधित विकास प्राधिकरणों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भवन ऊंचाई, सड़क चौड़ाई, यातायात, आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियों सहित महायोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और नियोजन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि ऋषिकेश जैसे धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए महायोजना केवल भूमि उपयोग का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के शहरी और आर्थिक विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा महायोजना में पर्यटकों की संख्या के साथ ही शहरी आबादी, यातायात दबाव और व्यावसायिक गतिविधियां को ध्यान में रखते हुए ऐसी विकास योजना तैयार करना जरूरी है, जो शहर के विस्तार को व्यवस्थित दिशा देने के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखे।

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सभी मदरसों को नियमित शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले में संचालित मदरसों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता देना शुरू कर दिया है।

हरिद्वार जिले के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बेसिक अमित कुमार चंद ने बताया कि अब तक जिले के 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा लगातार अन्य मदरसों की ओर से भी आवेदन और संबंधित दस्तावेज विभाग को प्राप्त हो रहे हैं। विभाग इन आवेदनों की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य सभी मदरसों को एक समान शिक्षा व्यवस्था के तहत लाना है ताकि समान शिक्षा व्यवस्था संचालित हो सके।

‘युवा संगम’ चरण-7

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के तहत ‘युवा संगम’ चरण-7 की मेजबानी का जिम्मा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंपा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तराखंड को इस चरण में पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ा गया है। कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के चयनित युवा पश्चिम बंगाल की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक उपलब्धियों को करीब से जानेंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल के युवा उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू होंगे। दोनों राज्यों के युवाओं के इस आदान-प्रदान का पूरा व्यय भारत सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।

युवा संगम चरण-7 के नोडल अधिकारी एवं पृथ्वी विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की विविधता को करीब से समझने के साथ ही विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों और संभावनाओं से परिचित कराना है।

स्नातकोत्तर प्रवेश

कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार नए पंजीकरण 4 सितंबर तक किए जा सकेंगे, जबकि प्रवेश प्रक्रिया 5 सितंबर तक पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय ने संबंधित अभ्यर्थियों, परिसरों, संबद्ध महाविद्यालयों व संस्थानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

श्री नंदा देवी महोत्सव

नैनीताल में श्री नंदा देवी महोत्सव 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस वर्ष 16 से 23 सितंबर तक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा की बैठक में मेले की तैयारियों लेकर चर्चा की गई। बैठक में नगर की साफ-सफाई के साथ ही स्वास्थ्य व भीड़ नियंत्रण पर भी चर्चा की गई। श्री राम सेवक सभा ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ दीपदान के लिए अपने घरों से दीपक लाने का अनुरोध किया है।

खाद्य पदार्थ

जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मिलावट पर रोक के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विशेष निरीक्षण अभियान चला रही है। जिसके तहत अलग अलग टीमों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की गई। रविवार को शिवालिक नगर, आर्यनगर, रानीपुर मोड़ और झबरेड़ा क्षेत्रों में किराना स्टोर, रिटेल दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बेसन, मैदा, साबुन, काली मिर्च, पोहा, खाद्य तेल, चायपत्ती, देसी घी, नमकीन और बिस्कूट समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर खाद्य

लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। वहीं खाद्य पदार्थों की पैकिंग और लेबलिंग में भी अनियमितताएं सामने आईं। इस पर संबंधित खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए।

मौसम

प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए देहरादून, बागेश्वर नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा व पौड़ी जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश में लगातार बारिश से जन-जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौसम और बारिश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन समेत सभी विभागों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आपदा की सूचना सभी जिले तत्काल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाएंगे।

और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर.....

भारत व उज्बेकिस्तान के बीच सहमति को लेकर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए हैं। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है— यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति की राह खुली।

नेपाल आपदा को लेकर अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है — नेपाल जल प्रलय : दर्द का अंत नहीं, अब तक 788 मौतें।

प्रदेश में मदरसों को लेकर जारी मुख्यमंत्री के बयान को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है — राज्य में बिना मान्यता चल रहे मदरसे होंगे बंद।

उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है — देहरादून से पहाड़ तक बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें।